भारत सरकार
कृषि एवं किसान कल्याण मंत्रालय
कृषि एवं किसान कल्याण विभाग

लोक सभा
तारांकित प्रश्न सं. 24
04 फरवरी, 2025 को उत्तरार्थ

विषय: राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन

*__24. श्री नरेश गणपत म्हस्के:__
__डॉ. श्रीकांत एकनाथ शिंदे:__

क्या कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) के तहत देश में प्राकृतिक खेती की पद्धतियों को अपनाने पर विचार किया है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या जैव-आदान संसाधन केन्द्रों की स्थापना से किसानों के लिए प्राकृतिक कृषि आदान की समय पर सुलभता सुनिश्चित होगी और इसका खेती की लागत और मृदा के स्वास्थ्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा, यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या प्राकृतिक कृषि पद्धतियों में किसानों के प्रशिक्षण और कृषि सखियों/सामुदायिक संसाधन व्यक्तियों की तैनाती से प्राकृतिक कृषि पद्धतियों को अपनाने में उल्लेखनीय तेजी आएगी और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम होंगे;

(घ) जलवायु स्थिरता संबंधी स्थानीय कृषि-पारिस्थितिकी सिद्धांतों पर एनएमएनएफ द्वारा ध्यान केन्द्रित किए जाने का क्या प्रभाव पड़ेगा और उसके परिणामों को मापने के लिए क्या कार्यविधि अपनाई गई है; और

(ड.) क्या मौजूदा योजनाओं और स्थानीय बाजारों से जुड़ाव के साथ NMNF के एकीकरण से किसानों की उपज के लिए ब्रांडिंग और विपणन के अवसरों में सुधार होगा है और यदि हां, तो उसके प्रभावी एकीकरण के लिए योजनाबद्ध उपायों का विवरण क्या है?

उत्तर

__कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री (श्री शिवराज सिंह चौहान)__

(क) से (ङ) विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है।

"राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन" के संबंध में दिनांक 04.02.2024 को उत्तर दिए जाने वाले लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 24 के भाग (क) से (ङ) के संबंध में विवरण।

(क) एवं (ख): जी हाँ । केंद्रीय मंत्रिमंडल ने 25 नवंबर 2024 को केंद्र प्रायोजित योजना के रूप में 2481 करोड़ रुपए (भारत सरकार का हिस्सा 1584 करोड़ रुपए और राज्यों का हिस्सा 897 करोड़ रुपए) के कुल परिव्यय के साथ राष्ट्रीय प्राकृतिक खेती मिशन (NMNF) को मंजूरी दी। मिशन का उद्देश्य प्राकृतिक कृषि पद्धतियों, प्राकृतिक इनपुट की तैयारी आदि पर व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों के माध्यम से प्राकृतिक खेती को बढ़ावा देना है।

इस योजना में विभिन्न राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों में 7.5 लाख हेक्टेयर क्षेत्र में 15,000 प्राकृतिक खेती क्लस्टर बनाने की परिकल्पना की गई है। प्रत्येक क्लस्टर लगभग 50 हेक्टेयर के समीपवर्ती क्षेत्र और लगभग 125 किसानों से बनाया जाएगा। इस योजना का मुख्य उद्देश्य किसानों द्वारा खेतों पर प्राकृतिक खेती के आदानों (इनपुट्स) का उत्पादन करना है। 10,000 आवश्यकता-आधारित जैव-आदान संसाधन केंद्र इन क्लस्टरों के किसानों के लिए प्राकृतिक खेती के आदान की आसान उपलब्धता में सहायता करेंगे, जिससे बाहर से खरीदे गए रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम होगी। प्राकृतिक आदानों के उपयोग से मिट्टी की उर्वरता में उल्लेखनीय वृद्धि होती है और समग्र इकोलॉजिकल बैलेन्स को बढ़ावा मिलता है।

(ग): इस योजना में प्रत्येक प्राकृतिक खेती क्लस्टर में दो कृषि सखियों/सीआरपी की तैनाती की परिकल्पना की गई है, ताकि किसानों को प्राकृतिक खेती के तरीकों के बारे में जानकारी दी जा सके और स्वयं सहायता समूहों, आंगनवाड़ी, ग्राम सभा, कृषि विज्ञान केंद्रों आदि को शामिल करके समुदाय में व्यापक जागरूकता पैदा की जा सके। इस योजना के तहत किसानों, वैज्ञानिकों, किसान मास्टर प्रशिक्षकों, कृषि सखी/सामुदायिक संसाधन व्यक्ति (CRP) आदि के लिए व्यापक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की परिकल्पना की गई है। किसानों के लिए ये प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा क्लस्टरों में कृषि सखियों/CRP की तैनाती प्राकृतिक खेती को अपनाने को बढ़ावा देगी।

(घ): प्राकृतिक खेती के सिद्धांतों और पद्धतियों का उद्देश्य स्थान-विशिष्ट कृषि-पारिस्थितिक पद्धतियों को बढ़ावा देकर कृषि में जलवायु स्थिरता को बढ़ाना है, जिससे रासायनिक आदानों पर निर्भरता कम हो और प्राकृतिक इकोसिस्टम मजबूत हो। यह बहु-फसल प्रणालियों, बायोमास मल्चिंग आदि के माध्यम से इन-सीटू सॉइल आर्गनिक के उत्पादन को प्रोत्साहित करके सॉइल हेल्थ और नमी की मात्रा में सुधार करने पर भी ध्यान केंद्रित करता है। प्राकृतिक खेती लाभकारी कीटों, पक्षियों और सूक्ष्मजीवों की

उपस्थिति को बढ़ावा देकर जैव विविधता को भी बढ़ाती है जो प्राकृतिक कीट नियंत्रण और परागण का समर्थन करते हैं। सॉइल हेल्थ में सुधार के साथ, प्राकृतिक खेती की पद्धतियां कृषि अनुकूलता को बढ़ाती हैं, जिससे किसानों को चरम जलवायु घटनाओं से निपटने में मदद मिलती है।

(ड.): मिशन के प्रभावशाली परिणाम के लिए, केंद्र और राज्य सरकारों की विभिन्न योजनाओं, जैसे कि कृषि एवं किसान कल्याण विभाग, ग्रामीण विकास विभाग, खाद्य प्रसंस्करण उद्योग मंत्रालय, पंचायती राज मंत्रालय, आयुष मंत्रालय, सहकारिता मंत्रालय और पशुपालन एवं डेयरी विभाग की अन्य योजनाओं के साथ कंवर्जेन्स की परिकल्पना की गई है। एक सरल भागीदारी प्रमाणन प्रणाली और प्राकृतिक रूप से उगाए गए रसायन मुक्त उत्पादों के लिए एक आम राष्ट्रीय ब्रांड का निर्माण, बाजार पहुंच और संपर्क को काफी बढ़ावा देगा तथा प्राकृतिक खेती को व्यापक रूप से अपनाने में मदद करेगा।

*****